

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: (० मार्च, 2015

विषय:-जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी में दरांती-मतियाली-बसन्तकोट-ढीलम मोटरमार्ग के निर्माण हेतु कुल 2.086 है० भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-245/सात-12/2014-15 दि०-27.12.2014 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-5437/रा०प०-भू०हस्त (द०म०ब०ढी०मो०मार्ग)/2015 दि०-16.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल, ग्राम एवं रा०उ०नि०क्षे० बसन्तकोट, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ ख०खा०सं०-13 के खसरा सं०-1 मध्ये 0.207 है०, 30 म० 0.108 है०, 73 म० 0.180 है०, 75 म० 0.106 है०, 87 म० 0.020 है०, 89 म० 0.055 है०, 90 म० 0.135 है०, 92 म० 0.155 है०, खाता सं०-1 के खसरा सं०-91 श्रेणी 10(2) रास्ता 0.020 है० कुल 09 खेतों की 0.986 है० तथा ग्राम फल्यांटी नॉन जेड०ए० खाता खतौनी सं०-14 श्रेणी 10(4)ब०न०आ० के खसरा सं०-399 म० 0.117 है०, 5 म० 0.054 है०, 607 म० 0.062 है०, 1021 म० 0.117 है०, 1256 म० 0.045 है०, 1338 म० 0.072 है०, 1340 म० 0.027 है०, 2730 म० 0.054 है०, 2732 म० 0.054 है०, 1021/2738 म० 0.189 है० ख०खा०सं०-12 श्रेणी 10(2) रास्ता के खसरा सं०-608 म० 0.020 है० तथा ख०खा०सं०-7 की श्रेणी 9(3)ड ब०का०आ० के खसरा सं०-689 म० 0.060 है०, 1020 म० 0.065 है०, 1935 म० 0.090 है० तथा 1937 म० 0.074 है० 15 खेतों की कुल 1.100 है० इस प्रकार उक्त दोनों ग्रामों के 24 खेतों की कुल 2.086 है० भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 /वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभाग परामर्श/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उस पर मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या- 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011 /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या- 2/5 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।